VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 3 0 AUG 2022 No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2212)

Name of Candidate	MANISHA		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	627862
Center	Delhi	Date	30/8/2022

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What do you understand by 'constitutionalism'? Highlight various ways in which the Indian Constitution underscores this principle. **(150 words) 10**

'संविधानवाद' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालिए।

संविधानवाद से आशय संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश के विकास व संचालन को बढ़ावा देना है। इसके तहत संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करने वाली नीतियों का निर्माण नहीं किया जाता है तथा ऐसी विधियाँ अवैध मानी जाती है।

संविधानवाद को रेखांकित करने वाले प्रावधान-

⇒ व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला कानून केवल संसद द्वारा ही बनाया जा सकता है।

⇒ केशवानंद वाद में स्थापित मूल संरचना के प्रावधानों के विरुद्ध बने कानून प्रभावी नहीं होंगे तथा उन्हें अवैध माना जाएगा

⇒ भारतीय विधायिका का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। जिसे संविधान संशोधन द्वारा भी प्रवर्तित नहीं किया जा सकता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⇒ 7वीं अनुसूची के तहत शक्तियों का विभाजन संविधानवाद का उदाहरण है जिसमें केंद्र व राज्यों को अपने क्षेत्रों में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है।

इस प्रकार भारत में संविधानवाद को अपनाया गया है जिसमें संविधान को सर्वोच्च माना गया है तथा कुछ प्रावधानों को मूल संरचना में शामिल किया गया है जिन्हें संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. The Competition Commission of India (CCI) effectively reflects a shift from the era of Licence Raj to a conducive regulatory ambience for enhancing consumer welfare by encouraging competition in the market. Discuss.

(150 words) 10

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने के लिए लाइसेंस राज के युग से एक अनुकूल नियामकीय परिवेश में स्थानांतरण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। चर्चा कीजिए।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने तथा स्वतंत्र व प्रभावी व्यापार नीतियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। CCI एक सांविधानिक आयोग है जिसे 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा Act के द्वारा स्थापित किया गया था।

कार्य :- प्रतिस्पर्धा को सीमित करने वाली नीतियों की पहचान करना

→ प्रतिस्पर्धा को गैर-कानूनी तरीके से अपने पक्ष में करने वाली कंपनी पर कठोर कार्रवाई करना

→ ऐसे परिवेश का विकास करना जिसमें सभी को समान अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त हो।

→ कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों के गठन को रोकना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का महत्व :-

→ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विकास से उद्योगों के विकास को बढ़ावा

→ उपभोक्ता को उचित मूल्य पर उत्पादों की प्राप्ति

→ प्रतिस्पर्धी माहौल के कारण गुणवत्ता सुधार में वृद्धि जिसका अंतिम लाभ उपभोक्ता को प्राप्त होगा

→ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता के उत्पादों का विकास जिसके निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगा जिससे उद्योगों की क्षमता व निवेश बढ़ेगा

→ नकारात्मक प्रभाव वाले समझौतों की समाप्ति से कुटीर व छोटे उद्योगों को संरक्षण प्राप्त होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Mention various initiatives taken for online delivery of judicial services in India. Also, discuss the challenges faced in their implementation.

(150 words) 10

भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए प्रारंभ विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

भारत में न्यायिक व्यवस्था पर अत्यधिक भार है तथा न्यायाधीशों की कमी दोहरी समस्या पैदा करती है। न्याय प्राप्ति को बढ़ाने हेतु ऑनलाइन रूप से न्यायिक सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाया गया है ताकि न्यायालय पर बोझ को कम किया जा सके।

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा शुरु की गई ई-कोर्ट योजना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जिससे निम्न लाभ प्राप्त होंगे जैसे-

→ ऑनलाइन रूप से केस की सुनवाई

→ अपने केस की स्थिति के बारे में ऑनलाइन सारी जानकारी प्राप्त करना

→ वकीलों से ई-परामर्श प्राप्त करना

→ भौतिक उपस्थिति की अपेक्षा ई-उपस्थिति से सुनवाई जल्दी होने की संभावना होती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ :- तकनीकी अवसंरचना का अभाव

→ कुशल कार्यबल की आवश्यकता से कम उपलब्धता

→ आम जनता की तकनीक व मोबाइल प्रयोग संबंधी ज्ञान व जागरूकता की कमी

→ राज्यों में बिजली, इंटरनेट संबंधी उपलब्धता में पाई जाने वाली असमानता जैसे बिहार में इंटरनेट कनेक्टिविटी दिल्ली की अपेक्षा काफी निम्न है।

→ ई-प्रशासन के विकास हेतु निवेश की कमी

अतः में कहा जा सकता है कि न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन सुपुर्दगी एक बेहतर प्रयास है जिसके समक्ष आने वाली समस्याओं को कम करने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Bring out the similarities and differences in the Bill of Rights in the Constitution of the United States and Fundamental Rights in the Constitution of India. **(150 words) 10**

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उपबंधित बिल ऑफ राइट्स और भारत के संविधान में मूल अधिकारों के मध्य समानताओं और भिन्नताओं को रेखांकित कीजिए।

भारत के संविधान में मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित होकर जोड़ा गया था। अमेरि-का के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को अपनाया है जो भारतीय मूल अधिकारों से ज्यादा विस्तृत है।

समानता के तत्व :-

1. कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत
2. जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21)
3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)
4. स्वतंत्रता का अधिकार
5. लिंग, धर्म एवं रंग के आधार पर विभेद की समाप्ति
6. मौलिक अधिकार हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

असमानता के तत्व :-

① अमेरिका में मौलिक अधिकारों के विस्तार की प्रासंगिकता की 2 आधार पर जाँच की जाती है - i) तार्किक आधार पर - मानवतावादी व तार्किक आधार पर
ii) वैधानिक आधार पर - (अधिकारों विस्तार करने की क्षमता संबंधित प्राधिकरण के पास है या नहीं इसका निर्धारण किया जाता है।

भारत में केवल प्राधिकरण के पास संबंधित मुद्दे संबंधी कानून बनाने की क्षमता देखी जाती है या नहीं।

② मौलिक अधिकारों के हनन पर भारत में उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है लेकिन अमेरिका में केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. It is often argued that the implementation of The Forest Rights Act (FRA), 2006 has so far been tardy and ineffectual. Discuss. **(150 words) 10**
प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहा है। चर्चा कीजिए।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनों में निवास करने वाली जनजातियों को वन उत्पादों व निवास वाली भूमि पर अधिकार प्रदान किया गया है. इस कानून का उद्देश्य जनजातियों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है.

वन अधिकार Act 2006 की विशेषता -

→ वनीय लोगों को गौण उत्पाद तक पहुँच व उनके विकास और विपणन द्वारा लाभ प्राप्ति का अधिकार

→ 4 एकड़ तक की निवास वाली भूमि पर मालिकाना अधिकार

→ किसी परियोजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की मंजूरी आवश्यक

→ गौण खनिजों के उत्पादन में ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक

→ निवासित भूमि से बलपूर्वक विस्थापन नहीं

→ सांस्कृतिक अधिकारों को भी मान्यता जैसे- पूजा स्थल, नदी, पवित्र स्थान आदि।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ :- कई राज्यों के द्वारा लागू नहीं करना

→ खनिज संसाधनों के लिए राज्य द्वारा अलग से कानून का निर्माण ताकि वन अधिकार एक्ट के तहत ग्राम पंचायत की मंजूरी न लेनी पड़े।

→ छत्तीसगढ़ व झारखंड जैसे जनजाती बहुल क्षेत्रों में कार्यान्वयन संबंधी अनियमितता पाई गई है।

→ नौकरशाही द्वारा जनजातिय हितों की अवहेलना करना

→ गौण उत्पादों के विकास में सरकार सहायता का विकास उत्पादों के विपणन को प्रभावित करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Explain the rationale behind the creation of a Social Stock Exchange in India. Do you think this move would boost social impact investing in the country? **(150 words) 10**

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे निहित तर्क की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस कदम से देश में सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा?

हाल में सेबी के द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया है। इसके सृजन के पीछे उद्देश्य सामाजिक कार्यों में निवेश को बढ़ावा देना है ताकि भारत के सामाजिक क्षेत्र में सुधार को सुनिश्चित किया जा सके।

सृजन का उद्देश्य :-

1) कॉर्पोरेट भागीदारी का सामाजिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाना
2) सामाजिक क्षेत्रों के प्रति जवाबदेही की भावना का विकास करना
3) प्रभावी लोकतंत्र के विकास हेतु सभी की भागीदारी आवश्यक होना
4) सामाजिक क्षेत्रों जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भारत की स्थिति में सुधार करना
5) मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार करना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सोशल स्टॉक एक्सचेंज से सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को बढ़ावा मिलेगा जिसका दोहरा लाभ प्राप्त होगा। पहला लाभ वंचित वर्गों को सुविधाओं की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर सोशल स्टॉक एक्सचेंज में किए निवेश का प्रयोग कंपनी अपने विज्ञापन में कर सकती है जिससे कंपनी की लोकप्रियता में वृद्धि होगी तथा बिना विज्ञापन के आर्थिक निवेश से लाभप्राप्ति में वृद्धि होगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The National Digital Health Mission (NDHM) has the potential to bring a new revolution in India's health sector in multiple ways. Explain.
(150 words) 10

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रक में कई तरह से एक नई क्रांति लाने की क्षमता है। व्याख्या कीजिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है ताकि इसकी कार्यक्षमता को बढ़ावा दिया जा सके।

एनडीएचएम की विशेषता:-

→ डिजिटल हेल्थ आईडी - इसके तहत सभी नागरिकों को आईडी प्रदान की जाएगी जिसमें उनकी बीमारी, उपचार संबंधी सारी जानकारी उपलब्ध होगी।

→ डिजिटल अवसंरचना द्वारा :- इसके तहत सरकारी व निजी अस्पताल संबंधी सारी जानकारी को शामिल किया जाएगा ताकि भविष्य में योजना निर्माण तथा प्रभावी कार्यान्वयन में इसकी मदद ली जा सके।

→ नेशनल डिजिटल डॉक्टर व नर्स संबंधी डेटा की प्राप्ति ताकि क्षेत्र के हिसाब से योजनाओं का निर्माण किया जा सके।

प्रभाव :- डाटा की बेहतर उपलब्धता से प्रभावी रूप से योजना निर्माण

- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में वृद्धि
- क्षेत्र में रोगों की प्रवणता के आधार पर योजना निर्माण व संसाधनों के आवंटन को बढ़ावा
- विशिष्ट रोगों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान में उपयोगी
- आयुष्मान योजना का प्रभावी क्रियान्वयन बढ़ेगा
- आयुष्मान योजना में रिसाव की प्रवृत्ति में कमी
- भारत में प्रमुख रोगों की पहचान तथा प्रभावित लोगों की संख्या का पता
- स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी नीति बनाने में इस डाटा का प्रयोग किया जा सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. While participation of private sector in the higher education system of India is a necessity, it creates issues that need careful redressal. Discuss. **(150 words) 10**

हालांकि भारत की उन्नतर शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक अनिवार्यता है, लेकिन यह ऐसे मुद्दे उत्पन्न करता है जिनका सावधानीपूर्वक निवारण किए जाने की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

भारत में उच्चतर शिक्षा में नामांकन का स्तर निम्न बना हुआ है जो लगभग 26% है तथा उच्चतर शिक्षा में बिना नामांकन बढ़ाए देश में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ाया नहीं जा सकता है. इसलिए निजी निवेश को बढ़ावा देना जरूरी हो जाता है.

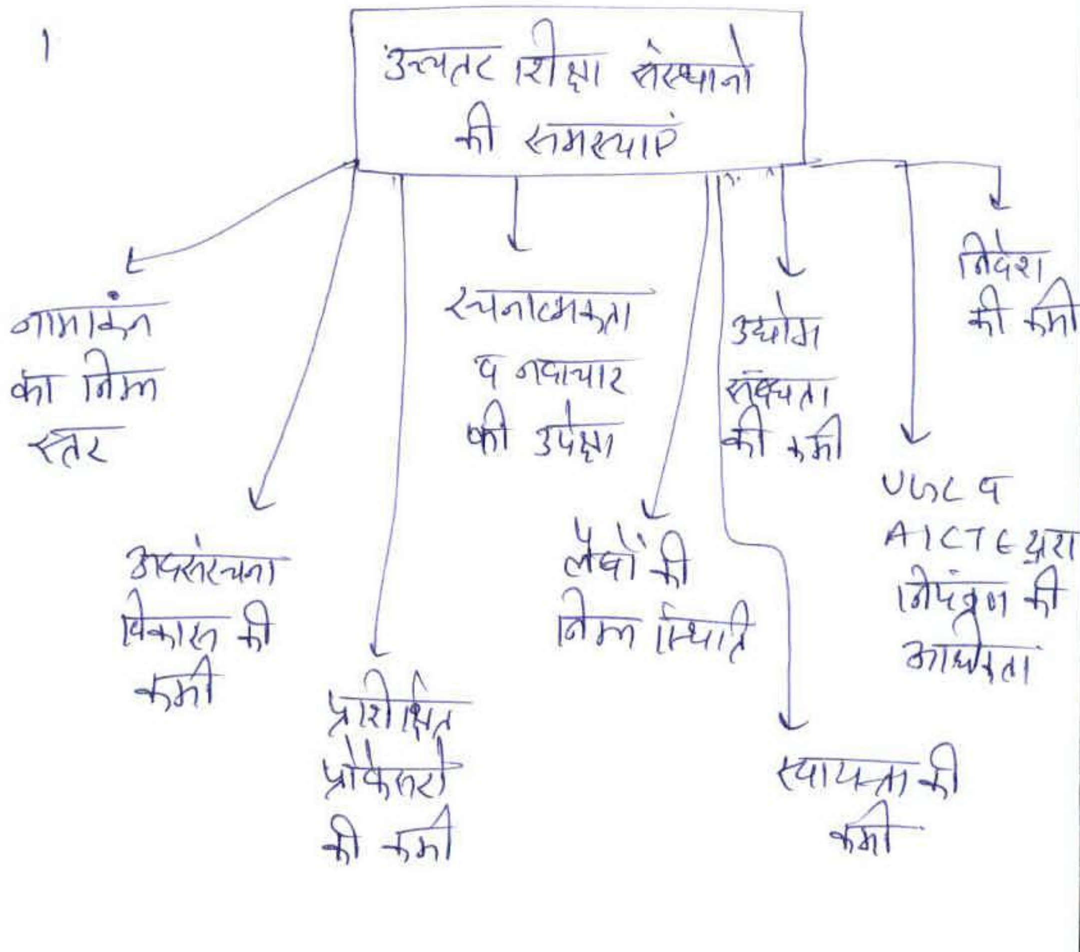

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निजी निवेश का प्रभाव :-

सकारात्मक

- निवेश में वृद्धि से अवसंरचना विकास को बढ़ावा
- उद्योग संबंधी रिसर्च को बढ़ावा जिससे दोनों क्षेत्रों को लाभ
- व्यापार व रचनात्मक गतिविधियों में वृद्धि
- नामांकन दर में वृद्धि को बढ़ावा
- वैश्विक स्तर की ब्रैंड का विकास
- विदेशों से छात्रों का भारत की तरफ शिक्षा हेतु प्रवास बढ़ेगा
- भारतीय संस्थानों का विकास अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के समान

नकारात्मक

- निजी निवेश लाभ प्रेरित होता है।
- फीस में अत्यधिक वृद्धि गरीब तबके को शिक्षा से वंचित कर सकती है।
- भारतीय संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण में कमी
- लाभ प्रेरित रिसर्च को अधिक बढ़ावा तथा मानव के लिए उपयोगी रिसर्च की उपेक्षा हो सकती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Highlighting the significance of Central Asia for India, discuss the challenges in strengthening the Indo-Central Asian relationship. **(150 words) 10**

भारत के लिए मध्य एशिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, भारत-मध्य एशियाई संबंधों को मजबूत करने के समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

भारत-मध्य एशीयाई राष्ट्रों के मध्य हाल ही में 5वीं संवाद बैठक का आयोजन किया गया था। जिसका उद्देश्य - भारतीय एवं मध्य एशीयाई राष्ट्रों के मध्य आर्थिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंधो को बढ़ावा देना ताकि दोनों को लाभ प्राप्त हो सकें।

मध्य-एशीयाई राष्ट्रों का महत्व -

(1) कजाकिस्तान से यूरेनियम की प्राप्ति से ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति

(2) मध्य एशीयाई देशों में भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना

(3) तापी-पाइपलाइन की सफलता बेहतर संबंधों पर निर्भर करती है

(4) भारत की मध्य एशीयाई राष्ट्रों तक पहुँच क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी तथा चीन को प्रतिसंतुलित करने में सहायक होगी

(5) उत्तर-दक्षिण गलियारे के द्वारा भारत की मध्य एशीया में मजबूत स्थिति बनाना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियां :-

⇒ अफगानिस्तान में तालिबान की उपस्थिति

⇒ मध्य-एशियाई राष्ट्रों में चीन द्वारा किया गया निवेश।

⇒ तापी परियोजना की सफलता पाकिस्तान से बेहतर संबंधों पर निर्भर।

⇒ गोल्डन ट्रायंगल द्वारा भारत में अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी

⇒ आर्थिक विकास का निम्न स्तर भारतीय निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

⇒ संघर्ष की स्थिति के कारण निवेश कम लाभदायक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Discuss the role that the Indian diaspora can play in the making of "Aatmanirbhar Bharat" (self-reliant India). Also, mention the challenges in this regard. **(150 words) 10**

"आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में विद्यमान चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए।

भारतीय प्रवासी बड़ी संख्या में विकसित एवं विकासशील दोनों देशों में उपस्थित है। तथा भारत के विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देते है।

आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय उत्पादों के विकास तथा विपणन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। ताकि भारत के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

'आत्मनिर्भर भारत' में प्रवासियों की भूमिका :-

⇒ 'प्रवासियों' भारतीय द्वारा भारतीय उत्पादों को वरीयता से निम्न लाभ होंगे
- उत्पादों की मांग बढ़ेगी
- भारत का औद्योगिक विकास बढ़ेगा
- विदेशी मुद्रा की प्राप्ति से निवेश में वृद्धि
- भारतीय उत्पादों की लोकप्रियता में वृद्धि
- लोकप्रियता से भारतीय उत्पादों के विकास को बढ़ावा मिलेगा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⇒ हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में निवास करने वाले भारतीयों हेतु अल्फांसो आम भेजे गए थे जिसका प्रभाव → स्थानीय लोगों द्वारा भी मांग की गई

↳ पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आम का निर्यात 2 गुना हुआ है जिसका लाभ भारतीय किसानों व निर्यातकों को प्राप्त हुआ

⇒ अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं को पूजा करने में प्रयोग होने वाले फूलों का निर्यात तमिलनाडु से किया गया है।

लाभ – भारत से जुड़ाव बढ़ेगा
– भारत का निर्यात बढ़ने से आर्थिक विकास होगा

11. A critical appraisal of the outcomes of the 74th Constitutional Amendment Act underlines the need for second-generation reforms to strengthen decentralisation of urban local governance in India. Discuss. **(250 words) 15**

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भारत में शहरी स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने हेतु दूसरी-पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चर्चा कीजिए।

74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तथा स्थानीय स्तर पर स्वशासन की स्थापना से विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था।

सकारात्मक प्रभाव -
- → स्थानीय संसाधनों के आधार पर योजना निर्माण
- → स्थानीय लोगों की योजना निर्माण में भागीदारी
- → नौकरशाही व आम जनता के बीच संवाद में वृद्धि
- → वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन
- → महिला व वंचित वर्ग की भागीदारी में वृद्धि.
- → विकेंद्रीकरण को बढ़ावा

नकारात्मक प्रभाव :-
- → वित्तीय संसाधनों की कमी

→ कर लगाने संबंधी अधिकारों का अभाव

→ योजना निर्माण में भागीदारी की कमी

→ नौकरशाही का लालफीताशाही रवैया व स्थानीय प्रशासन के प्रमुखों को महत्व नहीं देना

→ राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों को प्रभावित करना

→ स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण की अपेक्षा केंद्रीय व राज्य योजना हेतु कार्यरत

→ सीमित शक्तियां व वित्त की कमी

प्रयास :- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 200 शहरों को स्मार्ट बनाने का मिशन

→ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत वित्तीय साधनों की उपलब्धता को बढ़ाना

→ दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता बढ़ाना तथा छोटे व कुटीर उद्योगों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की स्थापना को प्रोत्साहन देना

→ लीड बैंक योजना के माध्यम से जिला स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा

प्रभाव

- → कार्यक्षमता में वृद्धि
- जवाबदेही में वृद्धि तथा दक्षता को बढ़ावा
- नागरिक अनुकूल सेवा विकास
- → नागरिक चार्टर के निर्माण को बढ़ावा
- प्रभावी स्थानीय स्वशासन की स्थापना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. It is argued that unchecked and rampant exercise of the power to insert laws in the Ninth Schedule results in undermining of Constitutional supremacy and creation of Parliamentary hegemony. Do you agree? Justify your stand with logical arguments. **(250 words) 15**

यह तर्क दिया जाता है कि नौवीं अनुसूची में विधियों को सम्मिलित करने की शक्ति के अनियंत्रित और व्यापक स्तर पर प्रयोग से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी और संसदीय आधिपत्य का सृजन होता है। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने मत की पुष्टि कीजिए।

9वीं अनुसूची में उन विधियों को शामिल किया जाता था जिन्हें अनुच्छेद 14, 19 व 21 के हनन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन्हें मूल संरचना के आधार पर भी असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता।

9वीं अनुसूची लाने उद्देश्य –

- भूमि सुधारों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना
- भूमि के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना
- बेहतर भू-धारण व्यवस्था का वितरण सुनिश्चित करना
- जमींदारी प्रथा का उन्मूलन
- काश्तकारी सुधारों को कानूनी मान्यता देना
- कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ाना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नकारात्मक पक्ष :-

⇒ संसद के द्वारा भूमि संबंधी कानूनों के अलावा भी अन्य कानूनों का इस सूची में डालना

⇒ न्यायिक पुनर्विलोकन व न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करता है

⇒ संविधान की मूल संरचना के ढाँचे की संकल्पना के विरुद्ध

⇒ कई राज्यों द्वारा भूमि संबंधी कानूनों के अलावा अप्रासंगिक कानूनों को भी इस सूची में डाला गया है।

⇒ संसद के अधिकार क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव हो

सकारात्मक पक्ष :-

⇒ कर्नाटक, केरल द्वारा भूमि सुधारों का प्रभावी क्रियान्वयन इसी का परिणाम है।

⇒ पश्चिम बंगाल में भूमि के न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा

⇒ सैकड़ों वर्ष पुरानी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन

⇒ काश्तकारों को भूमि संबंधी अधिकारों की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्राप्ति।

⇒ कृषि के न्यायसंगत वितरण में वृद्धि से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा

⇒ हरित क्रांति को सफल बनाने में सहायक

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि 9वीं अनुसूची ने संसदीय आधिपत्य को बढ़ावा दिया है। लेकिन किहोतो - होलोहन वाद के बाद 1974 के बाद में जोड़े गए 9वीं अनुसूची के कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जो संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Asymmetry is an important characteristic of federalism in India, which has helped in the accommodation of diverse demands inherent in our democracy. Discuss. **(250 words) 15**

असममिति भारत में संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसने हमारे लोकतंत्र में निहित विविध मांगों के समायोजन में सहायता प्रदान की है। चर्चा कीजिए।

संघवाद का भारतीय स्वरूप अन्य देशों जैसे अमेरिका एवं कनाडा से भिन्न है। भारत के संविधान में भारत को अनुच्छेद 1 के तहत 'राज्यों का संघ' कहा है तथा इस पर 2 कारणताएँ भी आरोपित हैं जैसे -
- ① भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं।
- ② संघ में शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर है।

भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति संबंधी विशेषता —

संघीय विशेषता →
- द्विस्तरीय शासन व्यवस्था
- केंद्रीय विधायिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व
- संविधान की सर्वोच्चता
- संविधान की कठोरता
- न्यायपालिका की सर्वोच्चता
- विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन
- एकीकृत न्यायपालिका

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

असमामित संघवाद के उदाहरण :-

1) आपातकालीन प्रावधान के तहत अनुच्छेद 352, 356 व 360 का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा करना

2) राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र के निर्देश न मानने पर प्रयोग

3) अखिल भारतीय सेवाएँ → कार्यरत - राज्य में
↳ अंतिम नियंत्रण - केंद्र सरकार द्वारा

4) राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा करना

5) 7वी अनुसूची के तहत महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को

6) अवशिष्ट शक्तियां भी संसद के अधीन

7) राज्य एवं केंद्र विधानों में विरोध की स्थिति में संसद विधान का मान्य होना

हाल ही में राज्यों के द्वारा अधिक शक्तियां प्रदान करने की मांग की गई है। पिछली अनुशंसा में सरकारिया आयोग के द्वारा भी की गई थी। राज्यों की मांग की पूर्ति हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं जैसे —

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(1) नीति आयोग का योजना आयोग के स्थान पर गठन जिसमें राज्यों की भागीदारी को बढ़ाया गया है।

(2) केंद्र से राज्यों को मिलने वाले हस्तांतरण को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 32% से 41% करना

(3) GST काउंसिल में राज्यों का प्रतिनिधित्व तथा राज्यों को 66% वोट की भारिता प्रदान करना

(4) केंद्रीय योजनाओं में कमी तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बढ़ावा देना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. In India, the Finance Commissions are established pursuant to the constitutional mandate. In this context, do you think the State Finance Commissions have been effective in promoting fiscal federalism? Substantiate with arguments. **(250 words) 15**

भारत में वित्त आयोगों की स्थापना संवैधानिक अधिदेश के अनुसार की जाती है। इस संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि राज्य वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं? तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए।

वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत शामिल किया गया है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केन्द्र व राज्यों के मध्य वित्तीय हस्तांतरण को प्रभावी बनाना। वित्त आयोग के निम्न कार्य है—

→ कर के शुद्ध आगमों की प्राप्ति का निर्धारण तथा राज्यों के मध्य वितरण होने वाले आगमों संबंधी नियमों को प्रतिपादित करना

→ राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने वाली अनुशंसा पर अपनी राय देना।

→ वित्त हस्तांतरण संबंधी नियमों का प्रतिपादन करना।

74वें संविधान संशोधन के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है जिनका प्रमुख उद्देश्य पंचायत व नगरपालिका

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने वाले नियमों का प्रतिपादन करना। साथ ही उन नियमों की अनुशंसा राज्य विधानमंडलों को करना।

राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में भूमिका -

① पंचायत व नगरपालिका संबंधित कानूनों के प्रतिपादन से वित्तीय स्थिति को बढ़ावा

② कर लगाने की क्षमता के विकास से स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी।

③ राज्य वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग से अनुशंसा करना सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाता है।

④ केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा स्थानीय प्रशासन संबंधी वित्तीय नियमों का प्रतिपादन राजकोषीय संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है।

हाल में 15वें वित्त आयोग द्वारा नगरपालिकाओं को स्वच्छता संबंधी मानकों के बेहतर प्रदर्शन करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो सहकारी संघवाद की राजकोषीय मजबूती दर्शाता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Reduction in the overall size of the bureaucracy has been seen as the underlying idea behind civil services reforms. Is it a good idea to reduce the size of the Indian bureaucracy? Examine in light of the experience of India.
(250 words) 15

नौकरशाही के समग्र आकार में कमी को सिविल सेवाओं में सुधार के पीछे अंतर्निहित विचार के रूप में देखा गया है। क्या भारतीय नौकरशाही के आकार को कम करना एक उपयुक्त विचार है? भारत के अनुभव के आलोक में परीक्षण कीजिए।

भारतीय नौकरशाही पर मोलन समिति द्वारा कई प्रकार की समस्याओं को दर्शाया गया है। जैसे - कार्यक्षमता की कमी, भ्रष्टाचार की विद्यमानता, जवाबदेही का अभाव आदि। नौकरशाही के आकार में कमी करने की अनुशंसा भी की गई है।

भारतीय नौकरशाही संबंधी मुद्दे :-

① पुरानी कार्यशैली पद्धति व नवाचार एवं रचनात्मकता का अभाव

② इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स द्वारा जारी रिपोर्ट में भारतीय नौकरशाही की रैंक 70 है जो काफी निम्न है।

③ भ्रष्टाचार में भी भारतीय नौकरशाही का प्रदर्शन निम्न है।

④ जवाबदेही, पारदर्शिता व अनुक्रियाशीलता का अभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नौकरशाही संबंधी आकार में कमी :-

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
→ आकार में कमी से उनकी दक्षता में वृद्धि के प्रयास बढ़ेगें	→ आकार में कमी व्यक्ति के कार्यभार में वृद्धि करेगी
→ बजट आवंटन का प्रयोग और तकनीकी रूप से सक्षम व रचनात्मक बनाने में किया	→ कार्यभार की अधिकता से मानसिक तनाव व अवसाद की समस्या
→ कम नौकरशाही से नियंत्रण बेहतर होगा।	→ अत्यधिक कार्य से प्रदर्शन में कमी आएगी तथा दक्षता प्रभावित होगी
→ राजस्व का कम व्यय जिससे अतिरिक्त बजट का उपयोग अन्य प्रभावी योजना में करना	→ एक व्यक्ति पर कई मंत्रालयों का कार्य से अतिव्यापन की समस्या
→ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कम नौकरशाही के बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं जैसे आस्ट्रेलिया	→ भ्रष्टाचार की संभावना में वृद्धि
	→ जवाबदेहिता में कमी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रयास:- कर्मयोगी मिशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना

→ केंद्रीय स्तर पर मानव संसाधन समिति द्वारा निरक्षण करना ताकि प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके।

2nd प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में भी नौकरशाही संबंधी दक्षता व प्रभावशीलता बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। जिन्हें लागू करने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. There is a need to ensure better ethical standards, accountability and management of temples in India. Discuss in the context of issues associated with state intervention in management of temples. **(250 words) 15**

भारत में मंदिरों के बेहतर नैतिक मानकों, जवाबदेही और प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। प्रत्येक राज्यों में सैंकड़ों मंदिर विद्यमान है। जिनमें से अधिकांश का प्रबंधन स्वयं मंदिर प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथा कई बड़े मंदिरों में अनियमितता भी पाई गई है।

मंदिर प्रबंधन संबंधी मुद्दे :-

① भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।
प्रभाव → सरकार की धार्मिक मामलों में प्रबंधन शक्ति को सीमित करना
→ मौलिक अधिकार के हनन पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रावधान

② समानता के अधिकार का हनन अनुच्छेद 14 का हनन है जैसे - सबरीमाला विवाद में महिलाओं का प्रवेश हेतु वर्जन समानता सिद्धांत के विरुद्ध है।

(3) कई मंदिरों में बड़े स्तर पर धन संपत्ति व सोने की उपस्थिति जिससे इसके गलत प्रयोग की संभावना भी बढ़ जाती है।
उदाहरण – साईं मंदिर में बड़े स्तर पर चढ़ावा व सोने का दान

(4) बड़े स्तर पर संपत्ति व आय की प्राप्ति लेकिन कर के दायरे से बाहर होना

(5) मंदिर का प्रयोग कई बार प्रभुत्वशाली लोगों द्वारा सत्ता के केंद्र के रूप में करना

उपाय :- मंदिरों में प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियम लाना ताकि प्रबंधन में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ सके।

→ एक निश्चित सीमा से ऊपर संपत्ति अर्जित करने वाले मंदिरों को कर दायरे में लाना ताकि प्रभावी प्रबंधन बढ़े।

→ सबरीमाला विवाद जैसे प्रावधानों में संविधान के अनुरूप प्रभावी प्रबंधन में वृद्धि करना तथा मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाना

→ मंदिर प्रबंधन समिति के समय-समय पर केंद्र द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक से अंकेक्षण कराना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रभाव – प्रभावी प्रबंधन से मंदिरों का संधारणीय विकास होगा जिससे पर्यटन में वृद्धि होगी

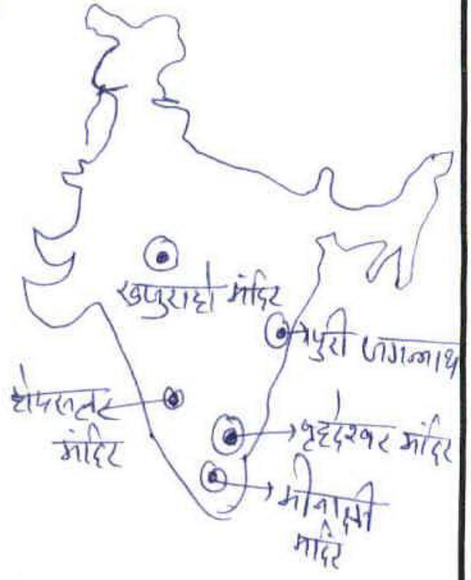

→ आय के स्रोत का नागरिकों को सुविधा प्रदान करने में प्रयोग

→ बेहतर प्रबंधन व्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक आकर्षित होंगे तथा भारत की आय में वृद्धि होगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. What do you understand by feminisation of old age? Highlight the issues associated with it in the Indian context. Also, mention the measures taken by the government in this regard. **(250 words) 15**

वृद्धावस्था के नारीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में इससे जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

वृद्धावस्था के नारीकरण से आशय वृद्धों की संख्या में नारीयों की अधिकता से है। भारत में वृद्ध महिला की जीवन प्रत्याशा वृद्ध पुरुष की अपेक्षा 2 वर्ष अधिक है। जिससे वृद्ध महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

कारण :-
- बढ़ता स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास
- रोगों के निदान में वृद्धि
- स्वास्थ्य अवसंरचना विकास में निजी व सार्वजनिक निवेश में वृद्धि
- पेंशन की उपलब्धता के कारण बीमारियों के इलाज हेतु निर्भरता में कमी
- पुरुषों की अपेक्षा प्राकृतिक रूप से महिलाओं में बीमारियों का कम होना
- ब्रेन स्ट्रोक व हृदय संबंधी रोगों का पुरुषों में अधिक 'प्रभाव'

संबंधित मुद्दे :- नारीकरण में वृद्धि से कई समस्या भी पैदा हुई है। जैसे-

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

⇒ वृद्धों के प्रति बढ़ता अपराधीकरण - शहरों में माता-पिता की वृद्धावस्था के कारण हत्या करना आम बनता जा रहा है।

⇒ वृद्धाश्रमों में माता-पिता को छोड़ने की प्रवृत्ति में वृद्धि

⇒ राज्य द्वारा स्वास्थ्य अवसंरचना पर निवेश अधिक होने से अन्य क्षेत्रों की अवहेलना

⇒ वृद्धों संबंधी रोगों में अनुसंधान की आवश्यकता

⇒ कार्यशील जनसंख्या पर कर भार में वृद्धि

⇒ वृद्धों में अवसाद, अकेलेपन की समस्या

सरकार द्वारा उठाए कदम :-

(1) इंदिरा गाँधी पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक सभी लोगों को पेंशन की प्रदायगी।

(2) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत आवश्यक उपकरणों तक वृद्धों की उपलब्धता सुनिश्चित करना

→ गरीब तबके तक मुफ्त वितरण करना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

~~(8)~~ प्रधानमंत्री वयोश्री योजना के तहत निवेश पर प्रोत्साहन प्रदान करना तथा कर संबंधी छूट प्रदान करना।

आगे :- सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार
→ वृद्धाश्रमों की स्थापना को बढ़ावा
→ GDP की 3% निवेश स्वास्थ्य क्षेत्र में करना
→ जरा-चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा
→ युवाओं में वृद्धों के प्रति जागरूकता व संवेदनशीलता बढ़ाना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Given its impact on both individual resilience and the resilience of the economy, is there a case for strong universal social protection in India? Discuss. **(250 words) 15**

व्यक्तिगत लचीलेपन और अर्थव्यवस्था की प्रत्यास्थता दोनों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, क्या भारत में सुदृढ़ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है? विवेचना कीजिए।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा से आशय सभी व्यक्तियों तक पेंशन, बीमा व स्वास्थ्य बीमा जैसे वित्तीय उत्पादों तक पहुँच को सुनिश्चित करना ताकि सुरक्षा के स्तर को बढ़ावा मिल सके।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा स्थिति –

→ भारत के 83% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत इसलिए पेंशन व बीमा की सुविधा प्राप्त नहीं।

→ भारत में बीमा कवरेज 26% है जो अधिकांश उच्च मध्यम क्षेत्रों तक सीमित

→ महिलाओं को मातृत्व लाभ की अदायगी में कंपनियों द्वारा प्रतिबद्धता नहीं दर्शाना

→ भारत में बेरोजगारी स्तर उच्च है तथा 22% जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत सरकार के प्रयास :-

(1) सामाजिक सुरक्षा संहिता Act 2019 - इसके तहत कई प्रकार के सुरक्षा Act को शामिल किया गया है। जैसे- मातृत्व लाभ Act व असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा Act 2008 आदि।

→ इसमें श्रमिकों की सभी श्रेणियों को शामिल जैसे - गिग, प्लेटफार्म, असंगठित श्रमिक आदि

→ सभी तक सामाजिक सुरक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना

(2) मातृत्व लाभ Act 2018 के तहत 6 माह के अवकाश का प्रावधान जिसमें सैलरी में कटौती का प्रावधान नहीं है।

उद्देश्य → माता व बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति को बढ़ाना

→ वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना

सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का प्रभाव -

(1) व्यक्तिगत :- व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर होगा

→ मांग में वृद्धि से बेरोजगारी में कमी

→ सीमा तक पहुँच सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र का विस्तार करेगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ व्यक्तिगत स्तर पर मानसिक तनाव में कमी क्योंकि पेंशन का प्रावधान इसमें शामिल है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:-

⇒ बीमा क्षेत्र में वृद्धि से लोगों की बचत करने की क्षमता विकसित

⇒ बचत का प्रयोग निवेश गतिविधि हेतु किया जाएगा

⇒ निवेश में वृद्धि आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा जिससे बेरोजगारी में कमी होगी

⇒ बेरोजगारी में कमी मांग में वृद्धि करेगी जिसका सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. There have been arguments that with the old global multilateral order failing to manage rising challenges, issue-based coalitions are gaining traction and have become the arenas of functional cooperation. Discuss. **(250 words) 15**

ऐसे तर्क दिए गए हैं कि पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था बढ़ती चुनौतियों का प्रबंधन करने में विफल रही है, जबकि मुद्दे-आधारित गठबंधन लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र बन गए हैं। चर्चा कीजिए।

पुरानी बहुपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत आईएमएफ एवं विश्व बैंक जैसे संस्थानों को शामिल किया जाता है। वर्तमान में कई घटनाओं के माध्यम से इस बात की स्पष्टता में वृद्धि हुई है कि ये संस्थान कई प्रकार की प्रबंधन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसे -

① डब्ल्यूटीओ में सुधार की मांग :- भारत, चीन जैसे कई विकासशील देशों द्वारा इस मांग को उठाया गया है तथा ऐसा माना जाता है कि WTO के निर्णय अमेरिका के पक्ष में झुके होते हैं।

② डब्ल्यूएचओ के वित्तीय सुदृढ़ता हेतु प्रयास -

हाल में WHO के द्वारा मांग रखी गई है कि WHO की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना चाहिए तथा विकसित देशों के द्वारा अपने अंशदान में वृद्धि करनी चाहिए।

③ UNFCCC के बाद भी G-20 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव कैन्या द्वारा प्रस्तुत करना - दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन हेतु की जाने वाली कार्रवाई का प्रभाव कम रहा है।

④ यूएनएससी में स्थायी सदस्यता हेतु प्रयास
- भारत द्वारा अपनी जीडीपी व जनसंख्या के आधार पर इसकी मांग करना
- जापान जैसे विकसित राष्ट्रों द्वारा भी मांग
- भारत की प्रतिद्वंदिता के कारण पाकिस्तान द्वारा भी मांग करना

बहुपक्षीय संस्थाओं की विफलता का प्रभाव :-

⇒ क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक व सांस्कृतिक संगठनों का गठन जैसे -
- बिम्सटेक की स्थापना दक्षिण एशिया व आसियान के मध्य व्यापार बढ़ाने।
- → सार्क की स्थापना दक्षिण एशिया में व्यापार बढ़ाना - उद्देश्य
- → इसी प्रकार आसियान आदि संगठनों का विकास हुआ

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⇒ WTO की विवाद निवारण संबंधी अप्रभाविता के बाद चीन के द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना करना

└→ प्रभाव - WTO की प्रभावशीलता में कमी
→ वैश्विक व्यापार में नियमों की प्रभावशीलता में कमी
→ देशों का WTO में विश्वास कम

आगे → समय के साथ बदलती वैश्विक स्थिति के अनुसार संस्थाओं में सुधार करना
→ भारत एवं चीन जैसे विकासशील राष्ट्रों के महत्व एवं स्थिति को महत्व देना
→ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ाने हेतु लगातार संस्थाओं की कमियों में सुधार करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India intends to achieve a balanced and optimal development of energy infrastructure in the South-Asian region through mutual understanding and cooperation. In light of this statement, discuss the need as well as existing gaps in South Asia's energy cooperation. **(250 words) 15**

भारत पारस्परिक समझ और सहयोग के माध्यम से दक्षिण-एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में एक संतुलन और उसका इष्टतम विकास सुनिश्चित करना चाहता है। इस कथन के आलोक में, दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता और इस संदर्भ में विद्यमान कमियों पर चर्चा कीजिए।

भारत की दक्षिण एशियाई में महत्वपूर्ण उपस्थिति है क्योंकि ऐतिहासिक कारणों के साथ सामरिक उपस्थिति तथा विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र में बढ़ता भारत का महत्व इसे महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है।

भारत का ऊर्जा के बुनियादी ढांचे विकास संबंधित प्रयास के कारण :→ भारत 2 बड़ा कोयला आयातक

→ अधिकांश पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस की आपूर्ति आयात द्वारा

→ सौर ऊर्जा क्षमता 46GW तथा कुल ऊर्जा का केवल 11% है

→ नवीकरणीय संसाधनों का क्षमता के हिसाब से कम प्रयोग

→ विस्तृत तटीय क्षेत्र के बावजूद ज्वारीय व तरंग ऊर्जा क्षमता का दोहन नहीं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत के प्रयास :-

(1) अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के तहत 'वन सन वन वर्ड वन ग्रिड' (OSOWOG) संकल्पना का प्रतिपादन

→ इसके तहत दक्षिण एशियाई ग्रिड स्थापना

→ पड़ोसी देशों को ग्रिड स्थापना हेतु सहायता देना

→ तकनीक की उपलब्धता बढ़ाना तथा हस्तांतरण में वृद्धि करना

(2) एशिया-पैसेफिक EDGE अवधारणा —

→ एशिया-पैसेफिक क्षेत्र में बुनियादी ऊर्जा अवसंरचना ढांचे का विकास करना

→ अल्पविकसित व तकनीक रूप से असक्षम देशों को सहायता देना

(3) दक्षिण चीन सागर में अन्वेषण गतिविधि

→ प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की खोज ONGC इंडिया कंपनी के द्वारा

→ भारत तथा निकटवर्ती देशों की ऊर्जा उपलब्धता बढ़ाना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

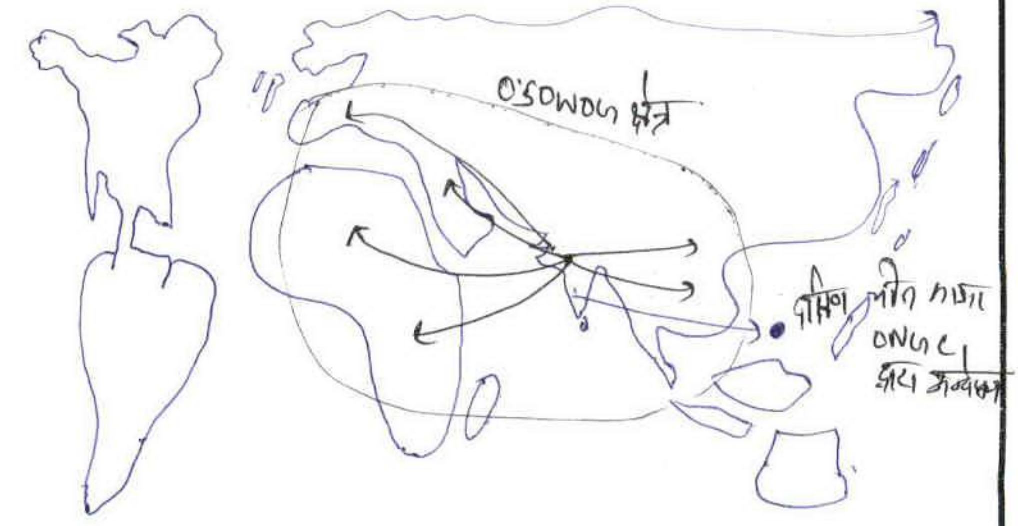

प्रभाव — क्षेत्र में ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि।

- आर्थिक विकास बढ़ावा
- जीवन स्तर बेहतर होगा
- तकनीकी विकास व अवसंरचना विकास में वृद्धि
- भारत का पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर।